

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 47 अंक 261 गुरुवार 16 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartyabasti.com

एक नजर

मनोनीत सभासदों को दिलायी शपथ



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। स्वामी लखन सिंह समारोह में नगर पंचायत स्वीची के लिए मनोनीत तीन सभासदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। एसडीएम स्वीची मनोज प्रकाश ने रंजना सिंह, सोहित अग्रवाल और विजय नारायण शिवारी को शपथ दिलाया।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने मनोनीत सभासदों से वादां में निर्वाचित सभासदों और अध्यक्ष के साथ सम्पन्न बनावर नगर पंचायत के विकास कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया। नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र ने सभी मनोनीत सभासदों को शपथ ग्रहण की बधाई दी और उनसे नगर पंचायत के विकास में योगदान देने की अपील की।

शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व सेशन में मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ईशो कीर्ति सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सत्येंद्र सिंह भोगू, स्वीची लोका समिति अध्यक्ष प्रदीप सिंह मिश्र, जिलासमीक्षा अधिकारी शर्म, शशि भूषण सिंह, विजय कुमार पांडेय राजू, नीलम गौड़, मंडल अध्यक्ष सुजीत सोनी, रामचन्द्र जायसवाल और प्रेम प्रकाश पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

नौ करी के नाम पर 7 लाख की ठगी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। नौ करी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपये की ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यह प्रकरण गौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जो वर उजागर हुआ जब पीडित को लंबे इंतजार के बाद भी निष्पत्ति पत्र नहीं मिला और उसने संबंधित विभाग से जानकारी ली।

आवास विकास कॉलोनी नौ, कोटावली, बस्ती निवासी कुशाग्र श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि अजय कुमार श्रीवास्तव और उनकी मां सुशीला देवी ने उन्हें सिंघाई विभाग में नौ करी दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने विभिन्न माध्यमों से उनसे कुल 7 लाख रुपये ठग लिए।

आरोप है कि पिछली अजय कुमार श्रीवास्तव और सुशीला देवी ने कुटुंबीय तरीके से एक फर्जी चयन सूची तैयार कर वादी को भेजी थी। उन्होंने कुशाग्र श्रीवास्तव को मई 2025 में निष्पत्ति पत्र दिलाने का आश्वासन भी दिया था।

समय बीतने के बावजूद जब निष्पत्ति पत्र नहीं मिला, तो पीडित को संदेश हुआ। उन्होंने संबंधित विभाग से सत्यता की जांच की, जहां पूरा मामला फर्जी निकला। इसके बाद जब वादी ने अपने बड़े वापस मांगे, तो आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।

इस संबंध में गौर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रकारों को पितृ शोक

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। प्रचारक जितेंद्र यादव के निधन रामकृष्ण यादव के आकस्मिक निवास से जनपद के प्रचारकों में शोक का माहौल है। प्रचारकों ने शोकसभा आयोजित कर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी और शोककण्डू परिवार को दुख की हथेली में साहस प्रदान करने के लिये श्रद्धांजलि प्रार्थना किया। रामकृष्ण यादव शहीद सत्यानंद सिंह स्टेडियम से सेवानिवृत्त हुये थे।

ट्रंप का दावा: ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा चीन

वाशिंग (आमा)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा चीन के सामने उठाया था, जिस पर उन्हें समझ मिला है। ट्रंप का कहना है कि कुछ हफ्तों में जब वह चीन जाएंगे तो राष्ट्रपति सी जिनपिंग उन्हें गले लगा लेंगे। ट्रुथ सोशल 'लेटकोम' पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि बीजिंग होंगकॉन्ग स्टेट को खुला रखने की उनकी कोशिशों का समर्थन कर रहा है।



किसी और से कही ज़्यादा बेहतर। इसके अलावा, ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के कार्यक्रम में सिद्ध किया है कि अमेरिकी एक घंटे के भीतर ईरान के सभी पुलों और बिजली संयंत्रों को तबाह कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिन पहले सीएस्तान के इस्लामाबाद में हुई अहम शर्तों वाला विलफ हो गई, जिसके बाद फिर से वार्ता का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। ईरान व अमेरिका के बीच पिछले डेढ़ महीने से युद्ध चल रहा है। हालांकि, अभी दो हफ्ते का सीजफायर है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से बड़े हमले रुके हुए हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया था कि

शिक्षा, रोजगार, यूजीसी के सवाल को लेकर मेधा ने दिया धरना



—बद हो शिक्षा का बाजारिकरण, मिले समान अवसर—
दिल्ली। युवाओं को मेधा के राष्ट्रीय प्रयास, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीन दयाल त्रिपाठी के संयोजन में यूजीसी का नया नियम वापस लिये जाने की मांग को लेकर बाग प्रतिमा के समर्थ धरना दिया। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मले ही नये नियमों पर रोक लगा दिया है किन्तु छात्रों और अभिभावकों में आशंका बनी हुई है। सरकार और यूजीसी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीन दयाल त्रिपाठी ने शिक्षा बचाओ-मैथिल बचाओ नारे के साथ शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सशर्णों की भी अन्य वर्ग के छात्रों की तरह ही समान अवसर देने की मांग की। कहा कि मेधा लगातार शिक्षा के सवाल और उसके बाजारिकरण के विरोध में संघर्षरत है। यह आन्दोलन चरणबद्ध ढंग से जारी रहेगा। कहा

पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर गिरा दिया दलितों का मकान



—दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई, दलितों को मकान बनाकर देने की मांग—
पत्र में कहा गया है कि लेखपाल वीरेंद्र कुमार पाण्डेय, नाथ तहसीलदार, दारोगा और पुलिस कर्मियों ने गत 13 अप्रैल को जिला कोठी और उच्च न्यायालय के निष्पत्ति की अवमानना करते हुये दलितों के कच्चे-पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया। उक्त लोगों ने गाटा संख्या 6111 में गांव के ही आ.पु.स. बन्दूक पुत्रगण मुनीलाल का अंधा अपहरण रखा दिया। मांग किया कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीत कर कार्रवाई की जाए।

सरकार की वादा खिलाफी से नाराज ग्रामीण बैंक कर्मी करेंगे आन्दोलन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में खास पहचान रखने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जहां एक ओर भारत सरकार ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहन पत्र मिल कर इन्हें मजबूत आर्थिक आधार दे रही है, वहीं दूसरी ओर इन्हें काम करने वाले लोगों अर्थात् ग्रामीण बैंक कर्मियों की जायज मांगों को भी नजर अंदाज किया जा रहा है। भारत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ग्रामीण बैंक कर्मियों को सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इन्फ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन (आरबीआ) ने भारत सरकार को हड़ताल की नोटिस भेज कर देश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है।

सीबीएसई हाई स्कूल में अपराइज के छात्रों ने बनाया कीर्तिमान



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। अपराइज ट्यूटोरियल के छात्र-छात्राओं ने सीबीएसई हाई स्कूल में सफलता का कीर्तिमान बनाया। कुबुवार को सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर निदेशक और शिक्षकों ने प्रशंसा व्यक्त किया। निदेशक अरुण कुमार और ऋषभ राज ने बताया कि हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में अंशिका चौधरी ने सर्वाधिक 93 प्रतिशत, आर्य 93 सानन राव 91, आकृति श्रीवास्तव, 90, अभिनव पाण्डेय 90 और यशस्वी चौधरी ने 89 प्रतिशत अंक प्राप्त



—दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई, दलितों को मकान बनाकर देने की मांग—
पत्र में कहा गया है कि लेखपाल वीरेंद्र कुमार पाण्डेय, नाथ तहसीलदार, दारोगा और पुलिस कर्मियों ने गत 13 अप्रैल को जिला कोठी और उच्च न्यायालय के निष्पत्ति की अवमानना करते हुये दलितों के कच्चे-पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया। उक्त लोगों ने गाटा संख्या 6111 में गांव के ही आ.पु.स. बन्दूक पुत्रगण मुनीलाल का अंधा अपहरण रखा दिया। मांग किया कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीत कर कार्रवाई की जाए।



बाबा साहब की जयन्ती पर ग्रामीण क्षेत्रों में उमड़े लोग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के जयन्ती अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक आयोजन किये गये। इसी अंके में भीम पाश्चात्या समिति द्वारा सांघोड विकास क्षेत्र को कुडिया अम्बेडकर पार्क से नरियाव, खडौला, परसा जाफर, सोमहटी, धिल्लौर, पटखौली, कनेली, पकरी नासिर, परसा हज्जाम, मुजहना, जमोह, देवरिया माफो, ओडवार, हदवा शुकल, बरला, गगाराम मंडरिया, तिरकपुर, प्लास्टिक कामलेखस, मलिकपुर, बायाथोर, मकडुलगाँव होते हुए संस्थापक अध्यक्ष रामशंकर आजाद, संस्थापक कोषाध्यक्ष मूलचंद आजाद के संयोजन में मुजली आजाद पहुंचे। जयरां की संस्था में लोग 'बाबा साहब अमर रहे' बाबा लखे मिशन अथोर, हम सब मिलकर करेंगे बापू, जयभौम आदि के नारे लगे रहे थे।

नवजात की मौत मामले में निजी मैक्स हास्पिटल सील

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
कुदरहा सीएससी में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के चर्चित मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कुदरहा को बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद संबंधित निजी सर्वेक्स हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, जबकि लापरवाही के आरोप में न्याय नर्स कुसुम के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।



राज्य स्तरीय जांच टीम की पड़ताल में बगल स्थित निजी अस्पताल में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं। इन्हें अनियमितताओं के आधार पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील किया। अधिकारियों का मानना है कि बिना मानक के इलाज और प्रक्रियाओं में लापरवाही इस पूरे प्रकरण में अहम कड़ी रही। यह मामला उपमुख्यमंत्री वृजेश पाठक के संज्ञान में आने के बाद एक

सफाईकर्मी के हत्यारों के गिरफ्तारी की मांग: संघ ने डीएम, एसपी को साँपा पत्र, दिया आन्दोलन की चेतावनी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। बुधवार को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने सफाईकर्मी विनय कुमार वगैरे को हत्यारों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को पत्र साँपा। इसके बाद जिलाधिकारी को संबोधित पत्र डीएम के प्रशासनिक अधिकारी को साँपा गया।



पत्र देने के बाद अजय कुमार आर्य ने बताया कि छात्रनी थाना क्षेत्र के अकला निवासी सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा इध्या विकास खण्ड क्षेत्र के बसदेवा कुंवर गांव में निवात है। गत 12 अप्रैल को गांव के निकट उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है।

पत्र देने के बाद अजय कुमार आर्य ने बताया कि छात्रनी थाना क्षेत्र के अकला निवासी सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा इध्या विकास खण्ड क्षेत्र के बसदेवा कुंवर गांव में निवात है। गत 12 अप्रैल को गांव के निकट उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है।

विमल कुमार आनन्द अध्यक्ष, सुरेन्द्र कुमार मंत्री बने

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कुदरहा को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय पर पशुधन सुरक्षा अधिकारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव सम्पन्न हुआ। चुनाव अधिकारी डॉ. फजील खान की देख रेख में सर्वसम्मत से विमल कुमार आनन्द अध्यक्ष, विजय कुमार उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र कुमार मंत्री, मानू प्रताप सिंह संयुक्त मंत्री, रामेंद्र जायसवाल कोषाध्यक्ष, शिवदास लेखा समर्थक निर्वाचित घोषित किये गये।



अधिवेशन में गूंगा पुरानी पेंशन, आठवे वेतन आयोग का मुद्दा

की मजबूती पर जोर दिया। नव निर्वाचित अध्यक्ष विमल कुमार आनन्द ने कहा कि देश और प्रदेश के कर्मचारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जायज मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल किये जाने और आठवे वेतन आयोग को शीघ्र लागू किये जाने को लेकर हमें निरन्तर संघर्ष तेज रखना होगा। उन्होंने निष्पत्ति प्रदाय अधिकारी संघ को जनपद स्तरीय समस्तसंघों के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास जारी है।

बाबा साहब की जयन्ती पर ग्रामीण क्षेत्रों में उमड़े लोग



आजाद, मूलचंद आजाद, विक्रम गौतम एडवोकेट, रंजीत कुमार गौतम, जिलाध्यक्ष रामा प्रवीण कुमार आदि ने कहा कि बाबा साहब आजाद जीने छुआरत, भेदभाव के विरोध में लड़ते और देर कुदले समाज को शिक्षित करते, संघर्ष करो का नम दिया। जब तक समाज में विभक्तता, भेदभाव है बाबा साहब सदैव प्रासंगिक रहेंगे। मानवता ही उनके लिए सबसे बड़ा र्थ था। समाज के लोगों को उच्च मानव जीवन से प्रेरणा देने की जरूरत है।

अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम अंधारपाल ने कहा कि देश और प्रदेश के कर्मचारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जायज मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल किये जाने और आठवे वेतन आयोग को शीघ्र लागू किये जाने को लेकर हमें निरन्तर संघर्ष तेज रखना होगा। उन्होंने निष्पत्ति प्रदाय अधिकारी संघ को जनपद स्तरीय समस्तसंघों के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास जारी है।

अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम अंधारपाल ने कहा कि देश और प्रदेश के कर्मचारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जायज मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल किये जाने और आठवे वेतन आयोग को शीघ्र लागू किये जाने को लेकर हमें निरन्तर संघर्ष तेज रखना होगा। उन्होंने निष्पत्ति प्रदाय अधिकारी संघ को जनपद स्तरीय समस्तसंघों के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास जारी है।

अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम अंधारपाल ने कहा कि देश और प्रदेश के कर्मचारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जायज मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल किये जाने और आठवे वेतन आयोग को शीघ्र लागू किये जाने को लेकर हमें निरन्तर संघर्ष तेज रखना होगा। उन्होंने निष्पत्ति प्रदाय अधिकारी संघ को जनपद स्तरीय समस्तसंघों के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास जारी है।

अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम अंधारपाल ने कहा कि देश और प्रदेश के कर्मचारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जायज मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाल किये जाने और आठवे वेतन आयोग को शीघ्र लागू किये जाने को लेकर हमें निरन्तर संघर्ष तेज रखना होगा। उन्होंने निष्पत्ति प्रदाय अधिकारी संघ को जनपद स्तरीय समस्तसंघों के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास जारी है।

"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेदेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 16 अप्रैल 2026 गुरुवार

सम्पादकीय

बढ़ती मंहगाई

यह विचित्र बात है कि एक ओर सरकार मंहगाई को नियंत्रण में रखने का दावा करती है, तो दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका सीधा असर आम आदमी पर जरूरी खर्च में कटौती और आर्थिक परेशानियों के रूप में देखने को मिल रहा है।

जब आय के साधन सीमित हों, तो आम आदमी की यही अपेक्षा होती है कि जरूरी वस्तुओं के दाम उसकी पहुंच में हों, ताकि परिवार के भरण-पोषण का संकट पैदा न हो।

मगर हाल के वर्षों में आमदनी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, जितनी तेजी से वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा मंहगाई मार्च में बढ़कर 3.4 फीसद हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.2 फीसद के स्तर पर थी। खबरों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न संकट के कारण खुदरा मंहगाई में वृद्धि हुई है। मगर सवाल है कि अगर सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित या स्थिर करने के लिए उचित कदम उठा रही है, तो फिर मंहगाई में उछाल कैसे आ रहा है?

भारत में बढ़ती मंहगाई (युद्धप्रसूति) आम नागरिकों के लिए एक गंभीर आर्थिक संकट है, जिसने दरियाई के बजट और जीवनयापन की लागत को बढ़ा दिया है। फरवरी 2026 में भारत की खुदरा मंहगाई दर बढ़कर 3.21: हो गई है, और आने वाले महीनों में इसके 5: से ऊपर जाने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और ईंधन की ऊँची कीमतों के कारण है। आम नागरिकों को क्रय शक्ति कम हो गई है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम किया जाए, खाद्य पदार्थों का बफर स्टॉक बढ़ाया जाए और आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जाए।

यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में स्तम्भे आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। आमदनी में स्थिरता और घटती क्रयशक्ति की स्थिति में चार आवश्यक वस्तुओं पर आम लोगों का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है, तो उनके लिए परेशानियां पैदा होना स्वाभाविक है। दरअसल, मार्च में मंहगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा रहा।

रिजर्व बैंक नीति तय करते वक्त खुदरा मंहगाई को ही आधार बनाता है। खुदरा मंहगाई से इस बात का पता चलता है कि उपभोक्ताओं की खपत और खर्च की स्थिति क्या है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक अपनी नीति तय करते वक्त खुदरा मंहगाई को ही आधार बनाता है। सरकार का दावा है कि खुदरा मंहगाई अभी रिजर्व बैंक के चार फीसद के औसत अनुमान से नीचे बनी हुई है। मगर, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर मंहगाई दर चार फीसद के दायरे से ऊपर जाती है, तो फिर कर्ज के सरता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में फरवरी की तुलना में मंहगाई दर का बढ़ना पश्चिम एशियाई संकट के शुक्राती प्रभाव का संकेत है। यानी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का मोर्चा फिर से खुलता है और यह स्थिति लंबे समय तक रहती है, तो आवश्यक वस्तुओं के दाम किफत तेजी से बढ़ेंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में आलू-प्याज और कुछ दालों की कीमतों की मंहगाई दर घटी है, लेकिन सोने-चांदी के आभूषण, नारियल, टमाटर और फूलगोभी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई।

बिजली, गैस और अन्य ईंधन श्रेणी में खुदरा मंहगाई मार्च में 1.65 फीसद रही, जबकि फरवरी में यह 1.52 फीसद के स्तर पर थी। यानी आम लोगों के लिए राहत कम और मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। यही नहीं, शहरी इलाकों में 3.11 फीसद की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मंहगाई दर 6.3 फीसदी रही, जहां रोजगार और आय के साधन सीमित होते हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सरकार ने मंहगाई पर नियंत्रण के लिए टोस उपाय नहीं किए, तो आने वाले दिनों में यह संकट और ज्यादा गहराएगा।

युद्ध, बच्चे और बदलती सामाजिक चेतना



-डॉ. रीतू सारस्वत-

प्रश्न यह नहीं है कि युद्ध कहाँ और क्यों हो रहे हैं, बल्कि यह है कि उन बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, जिन्हें हम स्वयं इस संसार में लाते हैं, और जब हम उनके जीवन और सुरक्षा की रक्षा नहीं कर पाते, तब सम्य समाज होने का हमारा दावा स्वतः ही कठघरे में खड़ा हो जाता है।

हाला ही में नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास में एंजेलो ऑफे मिनवा नाम से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें उन छोटे बच्चों की बनाई वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, जो ईरान के मिनवा शहर के एक स्कूल के मलबे से बचाने हुए हैं। ये चित्र उस त्रासदी के साक्ष्य हैं, जिसमें एक हमले के दौरान अनेक बच्चों और अन्य नागरिकों की जान चली गयी। यह प्रदर्शनी केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का मंच नहीं है, बल्कि उन बच्चों के दर्ज करने का माध्यम है, जो इस घटना के बाद बोलने के लिए जीवित नहीं रहे। इन चित्रों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि बयारकों के राजनीतिक और सैन्य संघर्षों के बीच बच्चों का जीवन सबसे परेश और सबसे असहनीय से नष्ट होता है। यह स्थिति किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था का संकेत है, जिसमें बच्चों का अद्विष्ट और सुरक्षा लगातार



उपेक्षित रहते हैं। यह केवल एक घटना का विवरण नहीं, बल्कि उस व्यापक वास्तविकता की ओर संकेत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए आकलन भी रेखांकित करते हैं। युनिसेफ द्वारा जारी हालिया आकलन में, 'युनिसेफ रेड्सड विद ईरान्स' चिह्नित 'एन सीजफायर ऑफर्स' पाथू डू रिबकरी के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि वर्ष 2026 के आरंभिक महीनों में ईरान में दर्ज शहरी हमलों और उनसे उत्पन्न मानवीय परिस्थितियों के दौरान 1100 से अधिक बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं, जो इन घटनाओं के प्रभाव बच्चों के जीवन पर लंबे समय तक बने रहने की आशा का है। युनिसेफ ने यह भी रेखांकित किया है कि इन परिस्थितियों का सबसे अधिक और सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ा है। वे न केवल शारीरिक क्षति का सामना कर रहे हैं, बल्कि भय, असुरक्षा और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात के साथ जीवन

जोने के लिए विवश हैं। युनिसेफ के अनुसार, जिन बच्चों का स्थान विद्यालयों और सुरक्षित पारिवारिक वातावरण में होना चाहिए था, वे आज विस्थापन, अस्थिरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनेक बच्चों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया है और जो जीवित हैं, उनके लिए सामान्य जीवन की संभावना भी गंभीर रूप से बाधित हो चुकी है। यह स्थिति केवल एक मानवीय संकट नहीं, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था की गहरी विफलता को भी रेखांकित करती है, जो बच्चों की सुरक्षा के दावों के बावजूद उन्हें सबसे अधिक असुरक्षित छोड़ देती है। यह स्थिति केवल वर्तमान परिदृश्य का संकेत नहीं देती, बल्कि उस गहरी त्रासदी की ओर भी इंगित करती है, जिसे सभ्य समाज ने अपनी आकांक्षाओं की आड़ में उपेक्षित कर दिया है। वर्ष 1956 में प्रकाशित पुस्तक 'नाइट' इस त्रासदी को समझने

के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आती है, जिसमें एरी विजेले ने अपने जीवन के उन अनुभवों को दर्ज किया है, जिन्हें उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में स्वयं जिया। ट्रांसिल्वेनिया के स्पिटे शहर में जन्मे इस बालक को 1944 में उसके परिवार सहित उसके निवास-स्थान से हटाकर अहिंसापूर्वक और बाद में बुचेनावल्ड जैसे यातना केंद्रों में भेज दिया गया। यह कृति केवल एक व्यक्ति की स्मृतियों का संकलन नहीं है, बल्कि उस व्यापक मानवीय संकट का प्रमाण है, जिसके एक बालक का बचपन, विश्वास और जीवन-बोध एक साथ विखंडित हो जाते हैं। विजेले लिखते हैं कि मैं उन लपटों को कभी नहीं मूल सकता, जिन्होंने मेरे विश्वास को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। मैं उस सनाटो को कभी नहीं मूल सकता, जिसने मुझे जीवन की इच्छा छीन लीय और मैं उन क्षणों को कभी नहीं

मूल सकता, जिन्होंने मेरी आत्मा को नष्ट कर मेरे सपनों को राख में बदल दिया। यह कथन केवल एक बालक की व्यक्तिगत स्मृति नहीं है, बल्कि उन असंख्य बच्चों की सामूहिक पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है, जो युद्ध और हिंसा के बीच अपने अस्तित्व से पहले ही विचित्र हो जाते हैं। युद्ध की त्रासदी का एक अन्य आयाम उस समय सामने आता है, जब हम 'ए डायरी ऑफ आ यंग गर्ल' को देखते हैं, जिसे एन फ्रैंक ने 1942 से 1944 के बीच, लगभग दो वर्षों तक, उस अवधि में लिखा जब वह अपने परिवार के साथ नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए एक बंद स्थान में छिपकर रहने के लिए विवश थी। लगभग 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच लिखी यह डायरी एक ऐसी बालिका के जीवन का सजीव दस्तावेज है, जो निरंतर भय, असुरक्षा और सीमित परिस्थितियों के बीच भी अपने सामान्य जीवन और सपनों को बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। एन फ्रैंक की मृत्यु के उपरांत यह डायरी 1947 में प्रकाशित हुई, और यह केवल एक बालिका की स्मृतियों का संकलन भर नहीं है, बल्कि उन असंख्य बच्चों के जीवन की प्रतिनिधि। कथा है, जिन्हें युद्ध ने असंभव ही समाप्त कर दिया।

इसी डायरी में यह लिखती है, 'आई बाद टू दू गो ऑन लिविंग इवन आफ़र मॉर्ट ड्यूट (मैं अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित रहना चाहती हूँ) यह केवल एक बालिका की संशयपूर्ण अभिलाषा नहीं है, बल्कि उन असंख्य अग्रणी जीवन की प्रतिनिधि है, जिन्हें युद्ध ने पूर्ण होने का अवसर ही नहीं दिया। यह पंक्ति इस तथ्य को अव्यंत स्पष्टता से सामने लाती है कि युद्ध बच्चों से केवल उनके वर्तमान ही नहीं छीनता, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाओं को भी जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है।

—लेखिका समाजशास्त्री हैं।

युवा भारत के लिये बेरोजगारी की चुनौती

-अमित शर्मा-

भारत को दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में गिना जाता है। लेकिन यही युवा शक्ति आज बेरोजगारी की गंभीर चुनौती से जूझ रही है। देश के बड़े शहरों की चमकदार सड़कों से लेकर छोटे कस्बों और तंग गलियों तक, काम की तलाश में भटकते युवा मिल जाएंगे। यह स्थिति केवल आर्थिक चिंता नहीं है, बल्कि सामाजिक असंतुलन और भविष्य की अनिश्चितता का संकेत भी है। बेरोजगारी का सरासल अब व्यक्तिगत समस्या से बढ़कर राष्ट्रीय चिन्मस का केंद्र बन चुका है।

राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़े इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। विभिन्न श्रम संकेतों और आर्थिक आकलनों के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर पिछले कुछ वर्षों में 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ी गई है, जबकि 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में यह दर 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच रही है। राज्य स्तर पर स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में युवा बेरोजगारी दर कई बार 20 से 25 प्रतिशत के आसपास तक दर्ज की गई है। यह अंतर बनाता है कि क्षेत्रीय असमताएँ इस समस्या को और गहरा बना रही हैं।

बेरोजगारी को अक्सर केवल नौकरियों की कमी के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुआयामी समस्या है। इसमें शिक्षा व्यवस्था की खामियां, कोशल और उद्योग की जरूरतों के बीच असंतुलन, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ शामिल हैं। देश में हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए आवश्यक व्यावहारिक कोशल से विंचित होता है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में केवल 40 से 50 प्रतिशत स्नातक ही रोजगार योग्य माने जाते हैं। यह स्थिति वताती है कि भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी रोजगार के अनुभव या कौशल के दालने में पीछे है।

इसके साथ ही, बेरोजगारी का एक बड़ा कारण अवसरों का असमान वितरण भी है। शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सीमित और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है, जबकि ग्रामीण



बेरोजगारी जैसी जटिल समस्या का हल किसी एक उपाय से संभव नहीं है। इसके लिए समय और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले, शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाना होगा, जिसमें व्यावसायिक और तकनीकी कोशल को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, स्थानीय स्तर पर कोशल विकास केंद्रों को मजबूत करना होगा, ताकि युवाओं को उनकी जरूरत और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके।

भारत में महिला श्रम भागीदारी दर अभी भी लगभग 25 से 30 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। सामाजिक नैरेम, सुरक्षा की चिंता और घरेलू गृहनिर्वाहों की प्रतिस्पर्धा में पिछड़े जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए महंगी कोशिश, उच्च शिक्षा और नेटवर्किंग के अवसर लगभग पहुंच से बाहर होते हैं, जिससे उनका प्रथम बाजार दर रह जाती है। हालांकि, इस संकट के बीच एक महत्वपूर्ण आविर्भाव स्वरोजगार और कोशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर झुकाव के रूप में उभर रही है। जब औद्योगिक रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, तब लोग अपने स्तर पर छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, सेवा कार्य और घरेलू उद्योगों के माध्यम से आजीविका के रास्ते तलाशते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का माध्यम भी बन सकती है। इसका प्रभाव, स्वरोजगार को अभी भी यांत्रिक संस्थागत समर्थन नहीं मिल पा रहा है।

महिलाओं की स्थिति इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दरअसल बेरोजगारी जैसी जटिल

समस्या का हल किसी एक उपाय से संभव नहीं है। इसके लिए समय और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले, शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाना होगा, जिसमें व्यावसायिक और तकनीकी कोशल को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, स्थानीय स्तर पर कोशल विकास केंद्रों को मजबूत करना होगा, ताकि युवाओं को उनकी जरूरत और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, जिससे छोटे उद्यमों की टिकाऊ व्यवसाय खड़ा कर सके। महिलाओं के लिए विशेष नीतियां और सुविधाएं विकसित करनी होंगी, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ सके। इसके अलावा, युवाओं को करियर मार्गदर्शन और मानसिक समर्थन देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि वे सही दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकें।

वास्तव में, बेरोजगारी केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी है। यदि देश की युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर नहीं मिले, तो हम विकास के एक मजबूत स्तंभ को खो रहे हैं। इसलिए समय की मांग है कि नीति-निर्माता, समाज और संस्थाएं मिलकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें, जहाँ रोजगार केवल एक अवसर न होकर हर व्यक्ति का अधिकार बन सके। तभी भारत अपनी युवा शक्ति को वास्तविक विकास की ताकत में बदल पाएगा।

मतदाताओं के नाम कटने का नफ़ा- नुकसान



-मजहर हुसैन-

इस बार तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का ही फार्मूला बनाया है, इसके तहत राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार और युवा सशर्त जैसी योजनाओं की नकल करते हुए भाजपा ने कम से कम चार ऐसी योजनाओं को शुरू करने का दावा किया है जिनके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने वैसे भेजे जायेंगे।

विलंबित वसत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दौर में तुलसी डालो की ऐसी योजनाओं की तुलना 'रेडिया बॉनेन' से करते रहे हैं लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर बढ़ रही है।

राजनैतिक विश्लेषकों की अगर माने तो बंगाल में अब पारम्परिक मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं से रोजगार के जीवन में मंहगाई, रीसर्डी गैर की फिल्लर और 'ए के दौरान काटने जाए नाम ही उनके लिए अब ज्यादा अहम हो चुके हैं।

इस बार चुनाव में ईरान - इजराइल युद्ध का भी खासा असर दिखने लगा है। पांच साल बाद 2021 के जितनी सभा चुनाव ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्थितियों बदरी हो चुके हैं इस बार वैसी ही चर्चा हो रही है।

किराहल मतदाता सूची के विशेष गहन पुरीकरण परकाशित करने के दौरान कट हुए नाम ही राज्यों का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, बंगाल के मतदाताओं को हमेशा सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी है। यदि देश की युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर नहीं मिले, तो हम विकास के एक मजबूत स्तंभ को खो रहे हैं। इसलिए समय की मांग है कि नीति-निर्माता, समाज और संस्थाएं मिलकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें, जहाँ रोजगार केवल एक अवसर न होकर हर व्यक्ति का अधिकार बन सके। तभी भारत अपनी युवा शक्ति को वास्तविक विकास की ताकत में बदल पाएगा।



चौराहों से लेकर नुककड़ तक चाय की दुकानों पर कई महीने पहले से ही चुनाव को लेकर बहस छिड़ जाती थी लेकिन इस बार तत्काली कानों अलावा है स शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं की प्रतिक्रिया सशर्त जैसी योजनाओं की नकल करते हुए भाजपा ने कम से कम चार ऐसी योजनाओं को शुरू करने का दावा किया है जिनके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने वैसे भेजे जायेंगे।

ममता बनर्जी की अचरी तरह से जानती है की उनकी पार्टी खासकर उत्तर बंगाल में काफी कमजोर है स यही वजह है कि उन्होंने अपना चुनाव अभियान की शुरूआत उत्तर बंगाल से किया है स यह अब तक एक दर्जन से अधिक रैलियों को उत्तर बंगाल में सन्धिगत कर चुकी है।

तृणमूल सूचों पर अगर यकीन करें तो इस बार वोटर्स में भाजपा और केंद्र सरकार के प्रति भी नाराजगी है इसलिए वह खांमोश है और इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पहले से अधिक सीटों पर विजय हासिल होगी।

उत्तर बंगाल के मतदाताओं को रिझाने के लिए पिछले दिनों प्र. आम्नडी नरेंद्र मोदी ने भी साथ बनाम क्षेत्र में जहां रैलियों को सम्बोधित किया वही मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए उरत गुजारी और लम्बा रोड थो फिकल उरत मतदाता की सामग्री लाय कोशिश के बाद भी टूटने का नाम नहीं ले रही है। वैसे उत्तर बंगाल को भाजपा का गढ़ माना जाता है लेकिन बलकल इस बार असम से सटे कुछ इलाकों में भारी उरतजागी के कारण उसकी स्थिति काफी कमजोर होगी।

नुवाय से पहले हर पार्टी बंद कर चढ़कर चुनावों के दावे तो करती है लेकिन चुनाव के बाद सच मूल जाता है। यही वजह है की राज्य के लोग इस बार चुनावी बादों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब देश में ही आखिर एक सन्धाह में मतदाता अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे है या चुपचाप अपना दम कर देंगे है।

